P: ISSN No. 2394-0344 RNI No. UPBIL/2016/67980 VOL.- X , ISSUE- IV July - 2025
E: ISSN No. 2455-0817 Remarking An Analisation

ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति: एक अध्ययन
Socio-economic Status of Women in Rural India: A Study

Paper Id : **20397** Submission Date : **2025-07-04** Acceptance Date : **2025-07-18** Publication Date : **2025-07-23**
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.16403948
For verification of this paper, please visit on http://www.socialresearchfoundation.com/remarking.php#8

ममता कराड़िया
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान
एपेक्स यूनिवर्सिटी
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध में ग्रामीण परिवेश में सक्रिय महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। वर्तमान दौर की महिलाएँ अब पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रही हैं। यह परिवर्तन महज एक सामाजिक परिघटना नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी बदलाव है, जिसे सरकार द्वारा संचालित विविध योजनाओं एवं पहलों ने गति प्रदान की है। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), महिला सशक्तिकरण अभियान, स्वयं सहायता समूह (SHGs), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), डेयरी विकास कार्यक्रम, कृषि विस्तार सेवाएँ, बैंकिंग एवं वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण, और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएँ प्रमुख हैं। इनका लक्ष्य महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि बदलाव की अगुआ ताकत बनाना है। शोध का मूल उद्देश्य यह आकलन करना है कि उपर्युक्त योजनाओं, प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग एवं संसाधनों की पहुँच ने कार्यरत महिलाओं के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाया है। द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर इन पहलों का समग्र, तुलनात्मक एवं विवेचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

In this research, a detailed analysis of the social and economic status of women active in rural areas has been done. Women of the present era are now stepping out of the traditional boundaries and taking strong steps towards self-reliance and leadership. This change is not just a social phenomenon, but a revolutionary change, which has been accelerated by various schemes and initiatives run by the government. These include National Rural Livelihood Mission (NRLM), Women Empowerment Campaign, Self Help Groups (SHGs), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), Dairy Development Program, Agricultural Extension Services, Banking and Financial Literacy Training, and schemes promoting women entrepreneurship. Their goal is to make women not just beneficiaries but the leading force of change. The main objective of the research is to assess how much positive change the above schemes, training, financial support and access to resources have brought in the lives of working women. A holistic, comparative and critical analysis of these initiatives has been done on the basis of data obtained from secondary sources.

मुख्य शब्द

ग्रामीण महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, उद्यमिता विकास, वित्तीय साक्षरता, आत्मनिर्भरता, सरकारी योजनाओं का प्रभाव।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Rural women, women empowerment, social and economic status, self help groups, National Rural Livelihood Mission, MNREGA, entrepreneurship development, financial literacy, self reliance, impact of government schemes.

प्रस्तावना

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात, विशेषतः विगत कुछ दशकों में, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। वे अब न केवल पारिवारिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही हैं, बल्कि डेयरी, कृषि, लघु उद्योग, बैंकिंग एवं सेवा क्षेत्र में अपने उद्यम और कौशल का परिचय दे रही हैं। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने उन्हें स्थायी एवं सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया है, वहीं बैंकिंग प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास योजनाओं ने उनमें नवाचार, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को जन्म दिया है। फिर भी, सामाजिक रूढ़िवादिता, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा की कमी और संसाधनों की विषम पहुँच आज भी कई महिलाओं की प्रगति में रोड़े अटका रही है। अतः महिला सशक्तिकरण को केवल योजनाओं की सीमित परिधि तक न बाँधकर, व्यापक सामाजिक चेतना, पारिवारिक सहयोग और समान अवसरों के निर्माण से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण भारत की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना, विशेषकर शिक्षा, निर्णय-निर्माण, एवं सामाजिक सहभागिता के संदर्भ में।

2. महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, आजीविका के साधन, वित्तीय स्वतंत्रता एवं सरकारी योजनाओं से लाभ की स्थिति का विश्लेषण करना।

3. सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना, जो ग्रामीण महिलाओं की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

साहित्य अवलोकन

1. ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति:

ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जो सामाजिक परंपराओं, पितृसत्तात्मक सोच, शिक्षा की कमी, और सीमित संसाधनों से प्रभावित होती है। यद्यपि भारत में महिलाओं को संवैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से उन्हें अब भी अनेक स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019-21) के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं में केवल 59% महिलाएं ही अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में सक्षम हैं, और मात्र 54% महिलाएं घरेलू वित्तीय निर्णयों में भाग लेती हैं, जो यह दर्शाता है कि उनके पास पारिवारिक निर्णयों में सीमित भूमिका है। साक्षरता दर महिलाओं की सामाजिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जनगणना 2011 के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 58.8% थी, जबकि ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता दर 78.6% थी। यह 20% से अधिक का अंतर इस बात को रेखांकित करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाएं अब भी बहुत पीछे हैं। शिक्षा की यह कमी सामाजिक जागरूकता, अधिकारों की जानकारी, और आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा, NSSO Time Use Survey 2019 के अनुसार, ग्रामीण महिलाएं प्रतिदिन औसतन 6 से 7 घंटे निःशुल्क घरेलू कार्यों में व्यतीत करती हैं, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, पानी लाना, और पशुपालन, जबकि इन कार्यों का कोई आर्थिक मूल्य नहीं आँका जाता।

सामाजिक निर्णयों और राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से भी ग्रामीण महिलाएं सीमित अवसरों का सामना करती हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है, और Ministry of Panchayati Raj (2021) के अनुसार, देश में लगभग 14 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWRs) पंचायतों में कार्यरत हैं। हालांकि, कई मामलों में वे मात्र 'रबर स्टैम्प' की भूमिका में होती हैं, और वास्तविक निर्णय उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य ही लेते हैं, जिसे "सरपंच पति" की संज्ञा दी गई है। हालांकि बीते दशकों में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं—जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)—जिनका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। MWCD Annual Report (2022) के अनुसार, NRLM के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ है। फिर भी, सामाजिक स्तर पर गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक असमानता की वजह से इन प्रयासों का व्यापक प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला है।

अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ है, परंतु अभी भी उन्हें सामाजिक निर्णयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, और राजनीतिक भागीदारी में वास्तविक समानता दिलाने के लिए समाज और शासन दोनों को मिलकर अधिक प्रभावी प्रयास करने होंगे।

2. ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति:

ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुआयामी है, जो उन्हें कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं के प्रबंधन, मनरेगा जैसे सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), तथा सूक्ष्म उद्यमिता के माध्यम से योगदान करने का अवसर देती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग (2021) के अनुसार, भारत में करीब 75% ग्रामीण महिलाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न हैं, लेकिन केवल 13% के पास ज़मीन का कानूनी स्वामित्व है, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) और कृषि बीमा योजनाओं का लाभ लेने में बाधाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB, 2022) के अनुसार, भारत में दुग्ध उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा महिलाओं द्वारा उत्पादित किया जाता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, परंतु डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं की औसत भागीदारी केवल 30-35% है।

मनरेगा (MGNREGA), जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत संचालित होता है, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने का प्रमुख उपकरण बन चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (2023) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत कुल मानव दिवसों का 57% महिलाओं द्वारा अर्जित किया गया, जो एक सकारात्मक संकेत है। मनरेगा में महिलाओं की औसत सहभागिता 2008 में 40% से बढ़कर 2023 में 57% हो चुकी है। इससे उन्हें पारिवारिक खर्चों में भागीदारी और निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हुआ है।

स्वयं सहायता समूह (SHGs) महिलाओं की सामूहिक आर्थिक सशक्तिकरण की धुरी बन चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM, 2023) के अनुसार, भारत में लगभग 10 करोड़ महिलाएं SHGs के माध्यम से विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों जैसे कि मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, अचार-पापड़ निर्माण, व हथकरघा उद्योग से जुड़ चुकी हैं। विश्व बैंक (World Bank, 2021) की रिपोर्ट के अनुसार, SHGs की महिलाएं औसतन ₹5,000 से ₹12,000 प्रति माह तक की आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता, व आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है।

महिला उद्यमिता के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की भूमिका भी अहम रही है। SIDBI (2022) के अनुसार, मुद्रा योजना के अंतर्गत वितरित कुल ऋणों में से 69% महिला उद्यमियों को मिले, जिनमें अधिकांश ने कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ, डेयरी, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग, व स्थानीय उत्पाद निर्माण में निवेश किया। इससे ग्रामीण महिलाएं स्वयं की पहचान बना रही हैं, परंतु बड़ी मात्रा में ये ऋण शिशु श्रेणी (₹50,000 तक) के अंतर्गत हैं, जिससे उनका व्यवसाय सीमित स्तर पर ही रह जाता है।

ग्रामीण महिलाओं की श्रमिक स्थिति भी विशेष ध्यान देने योग्य है। PLFS (Periodic Labour Force Survey, 2022) के अनुसार, ग्रामीण महिला श्रमिक दर लगभग 27.7% है, जो शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक है, किंतु इसमें अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) के अंतर्गत हैं, जहाँ उन्हें न तो सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी होती है। इसके साथ ही, NSSO Time Use Survey (2019) बताता है कि महिलाएं प्रतिदिन 6.4 घंटे अनपेड केयर वर्क में व्यस्त रहती हैं, जिससे उनके लिए औपचारिक रोजगार में भागीदारी की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। हालांकि सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं — राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS), सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, व स्टैंड अप इंडिया — जिनका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय समावेशन, प्रशिक्षण, एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। फिर भी जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का प्रभाव क्षेत्रीय असमानताओं, सांस्कृतिक रुकावटों और सूचना के अभाव के कारण सीमित रह जाता है।

3.ग्रामीण महिलाओं की प्रगति में सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक बाधाएँ:

ग्रामीण भारत में महिलाओं की प्रगति बहुआयामी चुनौतियों से घिरी हुई है, जिनमें सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक बाधाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के अंतर्गत पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक असमानता, रूढ़िवादी सोच, धार्मिक एवं पारंपरिक मान्यताएँ, तथा महिलाओं की भूमिका को केवल घर-परिवार तक सीमित रखने की मानसिकता प्रमुख हैं (Desai & Thakkar, 2007)। इन मान्यताओं के कारण बालिका शिक्षा की उपेक्षा, प्रारंभिक विवाह, घरेलू हिंसा तथा निर्णय-निर्माण में सीमित भागीदारी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, महिलाओं की आवाज़ को सार्वजनिक मंचों पर सुनने की परंपरा का अभाव और सामुदायिक निर्णयों में पुरुष वर्चस्व भी उनकी सामाजिक स्थिति को कमज़ोर करता है (Kabeer, 1999)।

आर्थिक बाधाओं की बात करें तो ग्रामीण महिलाओं को आज भी भूमि, संपत्ति और उत्पादन के संसाधनों पर सीमित अधिकार प्राप्त हैं। अधिकांश महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र में काम करना पड़ता है, जहाँ उन्हें उचित मजदूरी, कार्य सुरक्षा, मातृत्व लाभ या सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं (Agarwal, 1994)। वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में भी उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेषतः जब वे संपत्ति की मालिक न हों। स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं की जानकारी और पहुँच भी ग्रामीण महिलाओं तक सीमित है, जिससे वे अपने आर्थिक विकास की संभावनाओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पातीं।

संरचनात्मक दृष्टि से, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में बड़ी रुकावट है। सीमित परिवहन सुविधाएँ, असुरक्षित सार्वजनिक स्थान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, बाल देखभाल केंद्रों की कमी और प्रशिक्षण केंद्रों की गैर-उपलब्धता महिलाओं को अवसरों से वंचित रखती है (Planning Commission, 2011)। इसके अतिरिक्त, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच, डिजिटल साक्षरता की कमी, तथा तकनीकी प्रशिक्षण में महिलाओं की न्यून भागीदारी भी वर्तमान युग में उनकी प्रतिस्पर्धा को कम करती है।
इस प्रकार, ग्रामीण महिलाओं की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए केवल योजनाओं की घोषणा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवश्यक है कि इन बाधाओं की जड़ तक पहुँचकर उन्हें दूर किया जाए। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक समर्थन, नीति निर्माण में भागीदारी, तथा संस्थागत सुधारों को समाहित किया जाए। जब तक समाज की सोच में व्यापक

परिवर्तन नहीं आता और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक निर्णयों में समान भागीदारी नहीं मिलती, तब तक सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना अधूरी ही बनी रहेगी।

मुख्य पाठ

ग्रामीण भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास, सामाजिक न्याय एवं लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर मानी जाती है। भारत की कुल महिला जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है (Census of India, 2011)। ये महिलाएं कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, परिवारिक देखभाल, जल एवं ईंधन संग्रहण जैसे विविध कार्यों में योगदान देती हैं, लेकिन सामाजिक संरचनाएं, रूढ़िवादी सोच, शिक्षा की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता उनके विकास में प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019–21) के अनुसार, ग्रामीण भारत में महिला साक्षरता दर 58.8% है, जबकि पुरुषों की 78.6%, जो लिंग आधारित शिक्षा असमानता को उजागर करता है। साथ ही, केवल 14% ग्रामीण महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व है और महज 8% के पास बैंक खाता संचालन की स्वतंत्रता है (NSSO, 2020)। घरेलू कार्यों में उनकी हिस्सेदारी को आर्थिक श्रम की श्रेणी में न रखे जाने से उनके योगदान को अकसर उपेक्षित किया जाता है। International Labour Organization (ILO, 2019) के अनुसार, भारत की लगभग 92% महिला शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, परंतु उनमें से बहुसंख्यक को श्रम का समुचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वयं सहायता समूह (SHG) जैसी अनेक योजनाएं आरंभ की गईं हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD, 2022) की रिपोर्ट के अनुसार, NRLM के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं SHG से जुड़ चुकी हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास, वित्तीय साक्षरता और निर्णय-निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। फिर भी, जमीनी हकीकत में इन योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन एवं प्रभाव सीमित है, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं में। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिलाएं आज भी घरेलू निर्णयों में अंतिम निर्णय लेने से वंचित रहती हैं और महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य, वित्त, या शिक्षा से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता मात्र 59% है (NFHS-5)।

इन आंकड़ों और तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण भारत की महिलाएं आर्थिक रूप से श्रमरत तो हैं, परंतु उन्हें उनका सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य नहीं दिया जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि न केवल नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन हो, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक रूप से समानता का अधिकार, आर्थिक संसाधनों तक पहुँच, और निर्णय लेने की स्वायत्तता मिले।

निष्कर्ष

ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार की विभिन्न योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता, और महिलाओं की बढ़ती जागरूकता ने उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। अब महिलाएं केवल घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कृषि, डेयरी, उद्यमिता और स्थानीय प्रशासन जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। उनकी सहभागिता से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया संबल मिला है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि यदि उचित अवसर, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो ग्रामीण महिलाएं सामाजिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर समानता और सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर सकती हैं।

भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव

ग्रामीण महिलाओं के सतत सशक्तिकरण हेतु कुछ ठोस और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले, शिक्षा और वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को समझ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। भूमि और संपत्ति पर उनका कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है, जिससे वे विभिन्न कृषि और वित्तीय योजनाओं का लाभ ले सकें। SHGs और महिला उद्यमिता को बाजार तक सीधी पहुँच, तकनीकी प्रशिक्षण, और मध्यम एवं उच्च स्तर के ऋण की सुविधा प्रदान कर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, महिला प्रतिनिधियों को राजनीतिक प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, और समर्थन तंत्र देकर पंचायत स्तर पर उनकी भूमिका को मजबूत किया जा सकता है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने, सूचना के प्रचार-प्रसार, और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी भारत का "समावेशी और संतुलित विकास" का सपना साकार होगा, जिसमें ग्रामीण महिलाएं सशक्त भागीदार बनेंगी, केवल लाभार्थी नहीं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Census of India. (2011). Primary Census Abstract. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.*
2. *National Family Health Survey (NFHS-5). (2019–21). India Fact Sheet. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.*
3. *National Sample Survey Office (NSSO). (2020). Periodic Labour Force Survey. Ministry of Statistics and Programme Implementation.*
4. *Ministry of Women and Child Development. (2022). Annual Report on Women Empowerment Schemes. Government of India.*
5. *International Labour Organization (ILO). (2019). Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Brief. Geneva.*

6. *Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. Development and Change, 30(3), 435–464.*
7. *Census of India. (2011). Primary Census Abstract.*
8. *National Family Health Survey (NFHS-5). (2019–21). India Fact Sheet. Ministry of Health and Family Welfare.*
9. *National Sample Survey Office (NSSO). (2019). Time Use in India. Ministry of Statistics and Programme Implementation.*
10. *Ministry of Women and Child Development (MWCD). (2022). Annual Report.*
11. *Ministry of Panchayati Raj. (2021). Status of Elected Women Representatives in Panchayati Raj Institutions.*
12. *UN Women. (2018). Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development.*
13. *National Statistical Office (NSO), Time Use Survey 2019.*
14. *National Dairy Development Board (NDDB), Annual Report 2022.*
15. *Ministry of Rural Development, MGNREGA Management Information System, 2023.*
16. *Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, PM-KISAN Dashboard, 2023.*
17. *National Commission on Agriculture, Report on Women in Agriculture, 2021.*
18. *Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Mudra Report 2022.*
19. *World Bank (2021), "Empowering Rural Women Through SHGs in India".*
20. *Periodic Labour Force Survey (PLFS), Annual Report 2022-23.*
21. *National Rural Livelihoods Mission (NRLM), Progress Report 2023.*
22. *NABARD (2021), Status of Microfinance in India*
23. *Desai, N. & Thakkar, U. (2007). Women in Indian Society. National Book Trust.*
24. *Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. Development and Change, 30(3), 435–464.8*
25. *Agarwal, B. (1994). A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia. Cambridge University Press.*
26. *Planning Commission (2011). Report of the Working Group on Empowerment of Women for the 12th Five Year Plan. Government of India.*